जनता परेशान और सीएम उतरवाएंगे अपनी आरती

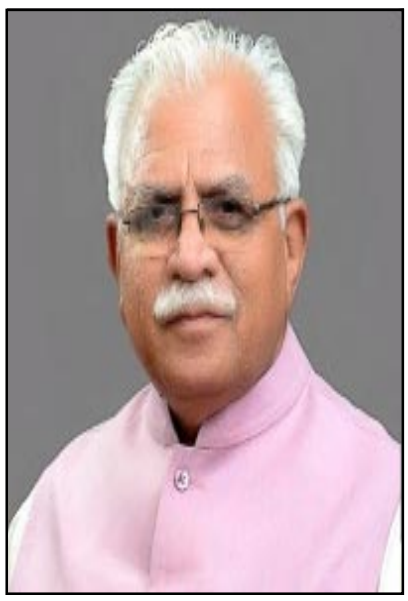

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पूर्णतया अयोग्य होते हुए भी राजसुख सुख भोग रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दिवाली मेले में नजर उतारो आरती की जाएगी। आम जनता बेरोजगारी-महंगाई से जूझ रही है और हमारे सीएम अपनी आरती उतरवाएंगे। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो जिस संघ से आते हैं उसमें आम जनता की समस्याओं से वास्ता नहीं रखा जाता बल्कि रामराज का सपना देखा जाता है जिसमें राजा प्रजा का पालनहार होता है न कि प्रजा का सेवक, और प्रजा उसकी आरती उतारती है।

भाजपा सरकारें जन कल्याण के काम करने से ज्यादा भव्य और आकर्षक कार्यक्रमों के जरिए भोली भाली जनता को गुमराह करने में ही विश्वास रखती हैं। बीते नौ साल में खट्टर सरकार प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी तो अच्छा नही कर सकी। चुनावी साल शुरू हो चुका है लेकिन खट्टर और उनके मंत्रियों के पास आम जनता के बीच बताने को कुछ नहीं है। ऐसे में खट्टर दिवाली मेले को भी अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सूरजकुंड मेला परिसर में तीन से दस नवंबर तक लगने वाले दिवाली मेले के दौरान सीएम खट्टर की नजर उतारो आरती की जाएगी।

खट्टर अपनी नजर उतारो आरती करवाकर अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे। भारत के वैज्ञानिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा विश्व में कर देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का लोहा मनवा रहे हैं तो खट्टर अपनी नजर उतरवा कर अंधविश्वास की वकालत करेंगे। राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि नजर उतारो आरती करवा कर खट्टर संघ-भाजपा की प्रतीकात्मक हिंदूवादी सत्ता का प्रचार कर बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के हथकंडे अपना रहे हैं।

आरती का नाम तो नजर उतारो आरती रखा गया है लेकिन इसे राजसी ठाठ बाट वाला भव्य रूप दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री को लंका जीत कर लौटे पुरुषोत्तम राम या महाभारत युद्ध की विजय के केंद्र भगवान कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारी कवायद 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है। जनता के पैसे बर्बाद कर प्रशासनिक अधिकारियों से आरती उतरवाने से बेहतर होता कि खट्टर ने ऐसे काम किए होते कि जनता खुद उनकी आरती उतारती, आगामी चुनाव में जनता उन्हें उतारेगी या उनकी आरती उतारेगी यह देखना होगा।

राज्य सेवा अधिकार आयोग ड्रामा बन कर रह गया है

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) महंगाई, रोजगार, विकास के मुद्दों पर नाकाम और नौकरशाहों की कठपुतली बने मुख्यमंत्री खट्टर अब जनता को राज्य सेवा अधिकार आयोग के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आयोग के चीफ कमिश्नर टीसी गुप्ता ने मंगलवार को हूडा कन्वेंशन हॉल में खुद मियां मिट्ठू बनते हुए बड़े-बड़े आंकड़े पेश कर आयोग की उपलब्धियां गिनाईं और अधिकारियों को जनता के आवेदनों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण का आदेश सुनाया।

टीसी गुप्ता के अनुसार राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं, योजनाओं आदि का लाभ लेने के लिए आम जनता द्वारा किए गए आवेदन का समय सीमा के भीतर निस्तारण कराना है। अपने गठन के नौ साल तक तो यह आयोग गुमनामी में रहा, शायद ही इसने कोई काम किया हो। अब चुनावी साल है और विकास, रोजगार, जनकल्याण के कार्य गिनाने को मोदी और खट्टर दोनों के पास कुछ नहीं है। ऐसे में राज्य सेवा अधिकार आयोग जैसी गैर जरूरी संस्था की बैठकें करवा कर सरकार अपनी झूठी उपलब्धियों के प्रचार का ड्रामा कर रही है।

राज्य सेवा अधिकार आयोग इसलिए गैर जरूरी है कि पूरे देश में सिटिजन चार्टर एक्ट 1997 से लागू है। इस एक्ट में सभी सरकारी विभागों में विभिन्न सेवाओं के आवेदन का कितने दिन के भीतर निस्तारण किया जाना है उसकी समय सीमा निर्धारित है। समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करने पर एक्ट के तहत संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

खट्टर यदि सच में जनता के हित में काम करना चाहते तो सत्ता में आने के साथ ही सिटिजन चार्टर को सभी विभागों में सख्ती से लागू करवाते। लेकिन उन्हें जनता के हित से नहीं बल्कि जुमले फेक कर अपना प्रचार करने से मतलब था, इसलिए राज्य सेवा अधिकार आयोग का गठन कर वाहवाही लूटी।

आयोग के गठन को नौ साल हो चुके हैं लेकिन आम जनता को आज भी राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन जैसी आधारभूत सेवाएं पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना सुविधा शुल्क चुकाए आसानी से काम नहीं होता। आयोग दफ्तरों में बैठे दलालों पर भी कोई अंकुश नहीं लगा सका है जो गरीब पात्रों को दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं सेटिंग गेटिंग से अपात्रों को दिलवा देते हैं।

आयोग होने के कारण राज्य सेवा का अधिकार आयोग के चेयरमैन किसी राजनीतिक संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन उन्होंने कन्वेंशन हाल में जिस तरह मुख्यमंत्री खट्टर की तारीफों के पुल बांधे उससे लगता है कि वह आयोग के चेयरमैन कम और सरकार के भोंपू अधिक हैं।

टीसी गुप्ता ने कन्वेंशन हॉल में लाखों आवेदन आने और उनका समयबद्ध निस्तारण किए जाने के दावे किए। उनके ये दावे जमीन पर तो कहीं नजर नहीं आते। आम जनता को सरकारी दफ्तरों में रोजाना चक्कर काटते हुए देखा जा सकता है। निकम्मे कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क पाए इनके आवेदन अटकाए रहते हैं और बैठकों में मशगूल जिला उपायुक्त या अन्य आला अधिकारियों के पास आम जनता को सुनने का समय नहीं है।

अगर राज्य सेवा अधिकार आयोग की कार्यशैली इतनी ही कारगर है तो आम जनता को विभागों के बजाय आयोग में ही सीधे आवेदन करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इससे जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक ही जगह समयबद्ध ढंग से उन्हें सेवाएं मिल जाएंगी।

लूट कमाई से फुरसत मिले तब तो करें विकास के काम

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जिला योजना स्कीम के तहत नगर निगम को आवंटित विकास कार्यों में एक भी काम शुरू नहीं हुआ है। काम के प्रति लापरवाही इतनी कि निगम का फर्जी डिग्री वाला एक्सईएन पद्मभूषण डीडीएमसी के वाइस चेयरमैन, जिला उपायुक्त की समीक्षा बैठक में भी शामिल होने की जहमत नहीं उठाता। जिला उपायुक्त ने निगमायुक्त को पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

जिला उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम को जिला योजना स्कीम के तहत वर्ष 2023-24 में 73 विकास कार्य आवंटित किए गए हैं। इसके लिए आवश्यक 529.82 लाख रुपये का फंड भी निगम को आवंटित किया जा चुका है। वित्त वर्ष समाप्त होने में मात्र पांच माह से भी कम का समय बचा है लेकिन 73 में से एक का भी काम अक्तूबर के अंत तक शुरू नहीं हो सका था।

जिला योजना के तहत ये सभी विकास कार्य क्षेत्र की जनता की मांग पर सांसद, विधायक जैसे जन प्रतिनिधियों की सिफारिश पर कराए जाने हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण जन प्रतिनिधि भी जनता की मांग वाले ये विकास कार्य जल्द पूरा कराए जाने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन नगर निगम के निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। डिवीजन एक के एक्सईएन पद्मभूषण तो जिला योजना के विकास कार्यों की बैठक में शामिल होने की जहमत नहीं उठाते।

एक्सईएन पद्मभूषण ही क्या निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी जब लूट कमाई से फुरसत पाएं तभी तो समीक्षा बैठक में भाग लें। आम जनता टूटी सड़कों, जलभराव, सीवर जाम, पेयजल आपूर्ति की समस्या से जूझती रहे एसडीओ से लेकर एक्सईएन तक किसी को कोई मतलब नहीं। निगमायुक्त भी इन निकम्मे अधिकारियों को निर्देश तो दे देती हैं लेकिन काम हो जाने की गांरटी नहीं दे पातीं। इन अधिकारियों की रुचि तो तोड़फोड़, अवैध निर्माण, कब्जा कराने वालों से सेटिंग गेटिंग कर मलाई खाने में रहती है।

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर बताया है कि एक्सईएन पद्मभूषण पिछली तीन समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे हैं। निगम को आवंटित 73 विकास कार्यों में अभी तक केवल 7 कार्यों के लिए टेंडर ही जारी किए गए हैं कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है। यही गति रही तो वित्त वर्ष में सभी विकास कार्य पूर्ण नहीं हो सकेंगे, ऐसे में आवंटित धनराशि लैप्स हो जाएगी और जन प्रतिनिधियों के बताए विकास कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।